[Shri V. Narayanasamy]

and in the name *ot* customs. This is a very serious thing People are suffering really. They leave their family for five or six years to earn their livelihood.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The association is becoming longer...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is a sensitive -matter. This concerns thousands and thousands of people of this country who go abroad to earn their livelihood. This happens when they come back. Therefore, I would like to tell the Minister of State for Finance that in the name of customs and other things they should not harass the passengers coming from abroad. The security people should not do this sort of a thing. I hope the Minister will take immediate steps to protect the people.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I wully associate myself with my colleague, While associating I want to mention one thing. The Central Government should not dismiss this saying that this is a State matter. Airports come under the National Airports Authority, which is under the Central Government. This problem is pertinent to all the States. In my State foreign tourists lose their hard currency, dollars. When a complaint is lodged, nothing is done. There are complaints lodged by the Embassies in Delhi also. So, I want this Govemment to take up this matter very seriously. I would request the Civil Aviation Ministry to withdraw the State PoKce and have their own police, like the Railway security force.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Whale associating myself with the Special Mention made by our senior colleague, Shri N. E. Balaram, I would say that this is true of every airport. Not only in Bombay, but we have also our experience in Calcutta. Mr. Balaram has spoken about jewelleries and Mr. Fernandes has spoken about Dollars, but at Calcutta Airport, even small things like Sarees and cigarette packets are not left out. A lady Officer, who was travelling' from Calcutta to Gauhati, while in the security check was asked from where she got the Sarees. Some other passenger was told why this much pack of cigarettes was there in his pocket. "That should not be there. Could I take out one?" This sort of harassment is there at ©very airport. We have our personal experiences at Calcutta Airport. So, I appeal to the authorities to take a serious note of it and make appropriate Inquiries and correcj" the position.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself and support what has been said.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I understand hon. Minister of State for Home, Shri Jacob, has discussed tffs matter with some of the MPs from Kerala. The Minister is also present here. This is not good for our country. I hope the Government will take appropriate action.

Move for Privatisation of N.J.M.C. Jute Mills

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल): सर, मैं आपके जरिए से इस हाउस की और गवर्नमेंट की तवज्जह इस मामले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि इस वक्त छह जूट मिलें हैं, जिनको सरकार चलाती है, जिसमें पांच पश्चिमी बंगाल में हैं और एक बिहार में है। यह बात सही है कि इन कारखानों में नुकसान हो रहा है और नुकसान हो यह कोई भी नहीं चाहेगा। इस पर कुछ दिनों से बहस-ब- मुबाहेसा जारी है।

अब अखबारों में यह खबर आ रही है कि सरकार इसको एक प्राइवेट इंडस्ट्री-लिस्ट को एजेण्ट बनाकर उसकी निगरानी में चलाने की बात सोच रही है। इस खबर से मजदूरों में बहुत परेशानी फैल गई है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के कोई कदम उठाने से पहले कारखानों की तमाम ट्रेड-यूनियनों के साथ बैठकर के इस पर बातचीत करने की जरूरत है।

यहां तक प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, उसका हाल तो और बुरा है। अभी मेरे पास एक लिस्ट है, जिसमें 15 कारखाने पूरे हिन्दुस्तान में बंद हैं और इन कारखानों के बंद होने की वजह

कहीं कच्चे पार्ट का ज्यादा दाम है और दूसरा यह है कि रूस से जो आर्डर आया करता था जब सोवियत यूनियन था वह, अब वहां पोलिटिकल सिचुएशन बदल जाने के कारण, आर्डर नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। पहले एक लाख टन अकेले रूस जाता था और दो लाख टन से ज्यादा मर्कजी गवर्नमेंट खरीदती थी अपने देश में बोराबंदी के लिए। लेकिन, यह भी समझ में बात नहीं आ रही है कि डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल ने आर्डर इतना कम क्यों कर दिया है? बज बज, एंग्लो इंडिया, कैल्विन, रिलाइन्स, श्री हनुमान, कामरहट्टी, फोर्टविलियम, आकलैंड, गंगेज, यह नौ जूट मिल पश्चिमी बंगाल में आज बंद हैं, कोई एक साल से, कोई छह महीने से, और कोई तीन महीने से, त्रिपुरा का सरकारी कारखाना त्रिपुरा जूट मिल भी बंद है।

आन्ध्र प्रदेश में चितिवलसा और नेल्लीमली जूट मिल है, यह दो कारखाने बंद हैं। मध्य प्रदेश में मोहन जूट कंपनी जो रायगढ में है, वह बन्द है और उत्तर प्रदेश में कानपुर में कानपुर जूट उद्योग है यह कारखाना भी बंद है। इस प्रकार यह 15 कारखाने हैं। तो प्राइवेट सैक्टर के मालिकान इन कारखानों को इसे चला नहीं पा रहे हैं। सरकारी कारखाने भी अगर प्राइवेट सैक्टर के हवाले किए गए तो इससे ज्यादा नुकसान की बात और कोई नहीं होगी। इसलिए यहां पर मंत्री जी मौजूद हैं, वे अगर रिएक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां के मजदूरों और 40 लाख पास के किसानों की रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है।

†[شری محمّد امین "مغربی بنگال": سر میں آپ کے ذریعہ سے اس ہاؤس کی اور گورنمنٹ کی توجہ اس معاملہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت چھ جوٹ ملیں ہیں۔ جن کو سرکار چلاتی ہے جس میں پانچ پشچمی بنگال میں ہیں اور ایک بہار میں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کارخانوں میں نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہو یہ کوئی نہیں چاہے گا۔ اس پر کچھ دنوں سے بحث و مباحثہ جاری ہے اب اخباروں میں یہ خبر آ رہی ہے کہ سرکار اس کو ایک پرائیویٹ انڈسٹریلسٹ کو ایجنٹ بنا کر اس کی نگرانی میں چلانے کی بات سوچ رہی ہے۔ اس خبر سے مزدوروں میں بہت پریشانی پھیل گئی ہے میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کارخانوں کی تمام ٹریڈ یونینوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کا سوال ہے اس کا حال تو اور برا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں ۱۵ کارخانے پورے ہندوستان میں بند ہیں اور ان کارخانوں کے بند ہونے کی وجہ کہیں کچے پارٹ کا زیادہ دام ہے اور دوسرا

†[ ] Transliteration in Aratie Script.

یہ ہے کہ روس سے جو آرڈر آیا کرتا تھا جب سوویت یونین تھا وہ اب وہاں پولیٹیکل سچوایشن بدل جانے کے کارن آرڈر نہیں آرہا ہے یا بہت کم آرہا ہے پہلے ایک لاکھ ٹن اکیلے روس جاتا تھا۔ اور دو لاکھ ٹن سے زیادہ مرکزی حکومت خریدتی تھی اپنے دیش میں بورا بندی کیلئے لیکن یہ بھی سمجھ میں بات نہیں آرہی ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آف سپلائی اینڈ ڈسپوزل نے آرڈر اتنا کم کیوں کر دیا ہے۔ بج بج اینگلو انڈیا کیسلون۔ ریلائنس شری ہنومان کمرہٹی۔ فورٹ ولیم۔ اک لینڈ۔ گنگیج۔ یہ نو جوٹ مل پشچمی بنگال میں آج بند ہیں کوئی ایک سال سے۔ کوئی چھ مہینے سے اور کوئی تین مہینے سے۔ تریپورا کا سرکاری کارخانہ تریپورہ جوٹ مل بھی بند ہے۔ آندھرا پردیش میں چتی ولسا اور نیلیمرلا جوٹ مل ہیں یہ دو کارخانے بند ہیں۔ مدھیہ پردیش میں موہن جوٹ کمپنی جو رائے گڑھ میں ہے وہ بند ہے اور اتر پردیش میں کانپور میں کانپور جوٹ ادیوگ ہے یہ کارخانہ بھی بند ہے۔ اس پرکار یہ [illegible] کارخانے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کے مالکان ان کارخانوں کو چلا نہیں پا رہے ہیں۔ سرکاری کارخانے بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کئے گئے تو اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس لئے یہاں پر منتری جی موجود ہیں وہ اگر ری ایکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں کہ یہاں کے مزدوروں اور ۴۰ لاکھ پاس کے کسانوں کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔

SHRIMATI KAMLA SINHA: ST, I also associate myself with his. special mention.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं भी एसो-सिएट करता हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) महोदय, , जूट के कारखानों का सवाल काफी गंभीर हो गया है । यह मेरे सहयोगी ने भी उठाया है । मैं इस मत का रहा हूं और हमारी नीति है कि जो भी कार-खाने बंद होने की स्थिति में हैं, चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह निजी हों, उनको बंद करने से पहले वहां के जो मजदूर संगठन हैं, उनसे बात करके यदि वे तैयार हों तो उनके हाथों में सौंप देना चाहिए । मुझे याद है, पश्चिमी बंगाल में । एक बजे बज जूट मिल है और दूसरे क नाम याद नहीं आ रहा है, यह दोनों आज से कई साल पहले तक बिल्कुल घाटे में चल रही थी । मजदूरों ने उसको ले लिया और अब पिछले डेढ़-दो साल से मजदूरों ने उसको फायदे में चलाना शुरू कर दिया तथा वे चलीं उसमें उन लो ने अपने फंड में से पैसा दिया, आदि-आदि । अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप घंटी बजा देंगे । लेकिन मेंठे सामने मुख्यत दो कारखाने हैं—एंग्लो-इंडिया जूट मिल्स और दूसरी है—एकर्स जूट वर्क्स । यह दो कारखाने तो ऐसे हैं जो बंद होने की स्थिति में हैं । इनको बी आई. एफ. आर. के हवाले किया गया है । लेकिन वहां के मजदूर संगठनों ने मांग की है

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

कि यह हमारे हवाले की जानी चाहिए तथा जो पिछली उनकी देनदारियां हैं, उसकी भरपाई सरकार करे तथा उनके ऊपर जिम्मेदारी न डाले और साथ ही जो आपरेटिंग एजेंट हैं उनको डायरेक्शन दे कि मजदूरों से बात करके फैसला करे। दूसरे, आई.डी.बी.आई की योजना है, जिनमें से वह सूद के बिना ऋण देते हैं। तो आई. डी. बी. आई. से इन लोगों को ऋण दिलाया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो बज बज जूट मिल्स है, उसका उदाहरण है कि जूट पैदा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी उनको एडवांस पैसा दिया और उसमें से उन्होंने जो तैयार माल था, वह लिया है। तो बहुत से इस प्रकार के माध्यम निकल सकते हैं। जिन दो मिलों का नाम मैंने लिया है-- एंग्लो-इंडिया जूट मिल्स और एंकर्स जूट वर्क्स, मजदूर इस बात पर राजी हैं कि वे अपने फंड में से 50 परसेंट पैसा देकर, वे 50 परसेंट शेयर्स ले लेंगे। खास तौर से इन दो कारखानों का और जैसा मेरे सहयोगी ने भी कहा, उनको भी इस प्रकार से देखा जाए। यह मैं जानता हूं कि मजदूर संगठन ऐसे हैं, जो कि मजदूरों के हाथ में कारखाना देने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन बहुत से संगठन ऐसे हैं जिन्होंने करके दिखाया है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस नीति में परिवर्तन लाए और खास तौर से जो पहले चल रहे हैं और जिन दो कारखानों का उल्लेख किया है, इनको तो मजदूरों के हाथ में दिया जाना ही चाहिए।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल) उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है और मंत्री जी यहां मौजूद हैं। सदन में जब भी कोई महत्वपूर्ण सवाल उठाया जाता है, आखिर वह किस लिए? एन. जे. एम. सी. की 6 मिलों को निजी मालिकान को बेचने का सवाल था। जब वह नहीं कर पाए तो आज एन. जे. एम. सी., उन 6 मिल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, उनको पानी की कीमत में बेचने के लिए एक निजी मालिक को सोल सैलिंग एजेंट बना दिया है। 6 सरकारी मिल प्रोडक्ट्स, एक जूट मिल के निजी मालिक खरीद कर बेचेंगे। नफा जो होगा, मुनाफा जो होगा, वह निजी मालिक को मिलेगा और एन. जे. एम. सी. में जो मिल्स हैं, सरकार यह कहेगी कि यह तो घाटे में चल रहे हैं। मंत्री महोदय, यह कहें, यह एश्यूरेंस दें कि किसी निजी मालिक को सोल सेलिंग एजेंट नहीं बनायेंगे। कोई निजी कारखाने में भी जूट मिल में कोई सोल सेलिंग एजेंट नहीं होता। चूंकि जूट मिल जो प्रोडक्ट्स वह आर्डर के मुताबिक बनाया जाता है, तो फिर उसको सेलिंग एजेंट बनाने की क्या जरूरत है।

شری محمد سلیم (مغربی بنگال): اپ سبھاادھیکش جی - یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور منتری جی یہاں موجود ہیں۔ سدن میں جب یہ بات - مہتوپورن سوال اٹھایا جاتا ہے۔ آخر کس لئے این۔ جے۔ ایم۔ سی کی ۶ ملوں کو نجی مالکان کو بیچنے کا سوال تھا جب وہ نہیں کر پائے تو آج این۔ جے۔ ایم۔ سی۔ ان ۶ ملوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کو پانی کی قیمت میں ایک نجی مالک کو سول سیلنگ ایجنٹ بنا دیا ہے۔ ۶ مل کے پروڈکٹس ایک جوٹ مل کے مالک نجی مالک کو خرید کر بیچیں گے۔ نفع جو ہوگا۔ منافع جو ہوگا۔ وہ نجی مالک کو ملے گا اور این۔ جے۔ ایم۔ سی میں جو ملیں ہیں سرکار یہ کہے گی کہ یہ تو گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ منتری مہودے یہ کہیں۔ یہ انشورنس دیں کہ کسی نجی مالک کو

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

سول سیلنگ ایجنٹ نہیں بنائیں گے۔ کوئی نجی کارخانے میں بھی جوٹ مل میں کوئی سول سیلنگ ایجنٹ نہیں ہوتا چونکہ جوٹ مل کا جو پروڈکشن ہے۔ وہ آرڈر کے مطابق بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو سیلنگ ایجنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) श्रीमन, यह सब पार्टियों की मांग है। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक कोने पर. हम भी एक कोने पर है। ऐसा मामला, मजदूरों का हित इसमें है तो कारखानेदारों को मुनाफा कमाकर देने के बजाय मजदूरों को उसका फायदा देना चाहिए।

Growing influence of militants in Janumi and Kashmir

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): MT. Vice-Chairman, Sir, I visited the State of Jammu and Kashmir with two other Members of the Lok Sabha on the 14th, 15th and 16th of August, A very serious situation has arisen in that State due to the faulty policies of the Central Government on a continuing basis. Infiltrators are pouring into Jammu and Kashmir from Pakistan. The population of the State of Jammu and Kashmir is increasing with these infiltrators. Innocent and loyal people like Gujjar Muslims are being beaten and killed. Oni 27-6-1992, a Gujjar boy from Village Chalhas, District Rajouri, was beaten and killed and even his dead body was not returned to his parents. As a result of the torture of Gujjar Muslims, not less than 400 families have crossed the border into Pakistan. Over 100 girls from the area of Surankote have slipped into Pakistan for trainnig. Eighty per cent of the police force is under the influence of the militants. If any infiltrator is caught by the military, he is handed over to the police and the police, after a brief enquiry, let him off. This is how infiltrators are let off.

Further, there is another alarming situation in the State. The State Government is financing certain newspapers which print anti-India material and encourage militancy. I have collected those papers. These are Urdu papers. Anybody can read them. The papers are "Alisafa", "Srinagar Times", "Aftab", "Vadi-ki-Awaz" and "Khidmat Press". The provincial financial corporation has advanced loans to the extent of one crore and thirty-seven lakhs of rupees to the first four papers. The fifth paper, "Khid_ mat Press", got Rs. 80 lakhs. They are publishing anti-India material and aire encouraging insurgency.

Another alarming situation is that the PT1/UNI agencies are now manned by those people who have been appointed with the recommendation of the militants. So wrong news are being given to the various newspapers. The foreign media is represented by no less than 172 persons as against two persons in 1947, all accredited and given all the facilities Mr, Doraiswamy got released on 21st August. It came in newspapers on 26th August, It is reliably learnt that not less than Rs. 10 lakhs was paid to the militants for the release; in addition, Rs. 1 lakh was paid *to* these papers only to print an advertisement saying, on behalf of the militants, "Thanks" and "Shukriya'.' This is surprising. And, all this amount is recorded in the Indian Oil Corootration records.

Lastly, Sir, Dr. Farooq Abdullah, in a recent statement, which is very damaging, has added fuel to fire. It should be view ed by the Government with all the seriousness as it is anti-India and amounts to betrayal of the trust of the people and' the nation.

All these constitute an explosive situation in the State of Jammu and Kashmir and heard the darkest clouds over the horizon of the State and the nation as a whole. And, .a ground seems to have been prepared for an attack by Pakistan. Through you, Sir, I warn the Government for preparedness full preparedness. They should prepare themselves more than 100 per cent to defend themselves and if necessary, destroy the training centres for Militants in Pakistan to protect the people *at the* country. Thank you.